Tactful Management Research Journal
Vol. 2 | Issue. 7 | April 2014
ISSN :2319-7943
Impact Factor : 1.5326 (UIF)

ORIGINAL ARTICLE

खुदरा कारोबार मे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग–''एक आकलन''

असलम सईद

विभागध्यक्ष वाणिज्य ए.के.एस.विश्वविद्यालय सतना(म.प्र)

***सारांश* :-**

भारत की 65: आबादी कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। विश्व में दूध उत्पादन मे भारत का स्थान प्रथम है तो फल एवं सब्जी के उत्पादन मे भारत दूसरे नम्बर में आता है किंतु देश मे पर्याप्त संसाधनों के न होने के कारण उत्पादन का लगभग 20: भाग नष्ट हो जाता है, कच्चा माल जैसे दूध – फल – सब्जी इत्यादि में हानि का ये प्रतिशत लगभग 40: तक पहुँच जाता है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की सहायता से भारत में खाद्यान तथा सीघ्र नाशवान पदार्थो के प्रसंस्करण की सुविधाऐ मुहैया कराई जा सकती है तथा खुदरा व्यापार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। वस्तुओ की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से भी प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग उपयोगी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के फैसले को देशहित में बताया तथा कहा कि इससे किसानों को उचित दाम मिलेगें, रोजगार मे वृद्धि होगी तथा छोटे – बड़े सभी कारोबारीयो को लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कम्पनियां प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के माध्यम से भारत के 130 करोड़ लोगो के विश्व के सबसे बड़े बाजार की ओर आकर्षित है तथा इससे प्रवेश पाने के लिऐ उत्सुक है ऐसी कम्पनियां बड़े पैमाने पर खरीदारी करके उन्हे कम दामो पर बेचने का साहस रखती है, क्योकि इनके पास साधनों की कमी नही है। वॉलमार्ट जैसी कम्पनी विश्व के अनेक देशो मे इसी नीति पर कार्य कर रही है क्योंकि ऐसा करने से उसका बाजार पर एकाधिकार स्थापित होता है जब वह वस्तुओं की कम दामों में बेचेगे तो कम पूंजी वाला छोटा कारोबारी उनके समक्ष बाजार में टिक नही पाऐगा और देखते – देखते उनके व्यापार बंद हो जायेगें और वे बेरोजगार हो जोयेगें। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से खुदरा व्यापार की दुनिया में सकारात्मक क्रांति आने की उम्मीद है आशा है कि देश के लिऐ खुदरा व्यापार एक फायदे का सौदा साबित होगा क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से विदेशी निवेशक और निवेश हासिल करने वाले देश दोनो को ही लाभ प्राप्त होने की संभावना है । यह नियम निवेशक को नये बाजार में प्रवेश करने और उसे लाभ कमाने का मौका देगा। बाकी तो आने वाला समय ही बताऐगा कि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग देश के लिऐ फायदे का सौदा साबित होता है अथवा यह देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाऐगा।

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध में द्वितीयक समंक के माध्यम से विभिन्न मैगजीनो के आर्टीकल्स समाचार पत्रों के लेख तथा विभिन्न समाचारों से प्राप्त जानकारीयों के आधार पर ये जानने का प्रयास किया गया हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का स्वरूप कहीं ईस्ट इण्डिया के स्वरूप से मिलता जुलता तो नही है।

भारत मे नये आर्थिक सुधार लाने के उद्देश्य से यू.पी.ए. सरकार के द्वारा 5 दिसम्बर 2012 को एक ऐतहासिक निर्णय लेते हुये मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस करार के अनुसार अब विदेशी मल्टी ब्रांड कम्पनियां भारत में आकर , भारत में स्थापित कम्पनियों के साथ मिलकर व्यवसाय कर सकती है इस मजूंरी से देश के लगभग 590 अरब डालर वाले खुदरा क्षेत्र में वॉलमार्ट, केरफोर, टेस्को जैसी कम्पनियों को भारत में आकर अपने व्यवसाय को चलाने के लिये तथा भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त किये जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। किन्तु इस अनुमति को प्रदान करते समय सरकार ने कुछ शर्तो को जोड़ दिया है जो निम्नलिखित है–

(1) प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (FDI) के अर्न्तगत भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी कम्पनीयो को कम – कम 10 करोड़ डालर का निवेश अनिवार्य रूप से करना होगा।
(2) F.D.I के अर्न्तगत प्रत्येक बार किये जाने वाले निवेश की राशि का 50% बैक एंड में लगाये जाने की शर्त है अर्थात निवेश का 50% बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किये जाने का प्रावधान है।
(3) 10 लाख डालर से अधिक के कारोबार हो जाने की दशा में ऐसा कारोबार के SME का दर्जा समाप्त कर दिया जाऐगा ।
(4) F.D.I के अर्न्तगत खुदरा व्यापारी अपने स्टोर को केवल उन्ही शहरों मे स्थापित कर पाऐगें जहाँ की जन– संख्या 10 लाख से अधिक है।
(5) FDI के अर्न्तगत खुदरा व्यापारी का अपने व्यवसाय से सम्बन्धित माल का 30% हिस्सा लघु एवं मध्यम उद्योगो से क्रय किया जाना आवश्यक होगा।
(6) FDI के अर्न्तगत विदेशी कम्पनीयो की हिस्सेदारी किसी भी दशा में 51% से अधिक नही होगी ।

Please cite this Article as : *डा. असलम सईद*, "*खुदरा कारोबार मे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग–''एक आकलन''*" : Tactful Management Research Journal (April ; 2014)

(7) FDI के अर्न्तगत प्रांरभ मे ऐसे खुले क्षेत्रों में कार्यरत फर्मो को ही विदेशी विनियोग की अनुमति प्रदान की जाऐगी जिनमे विदेशी निवेश के नियंत्रण एंव निगरानी की आवश्यकता नही होगी, अर्थात् कृषि बागान प्रिंट मीडिया; एवं रियल इस्टेट आदि में संलग्न व्यवसायों को विदेशी निवेश की अनुमति नही होगी।
(8) सरकार के इस निर्णय के पश्चात विदेशी कंपनिया भारत मे भी अपने स्टोर खोल सकेगी लेकिन इसके लिये राज्य सरकार की अनुमति भी आवश्यक है अर्थात राज्य सरकार जब तक किसी विदेशी मल्टी ब्रांड रीटेल स्टोर को खोले जाने की सहमति प्रदान नही करती तब तक उस राज्य मे विदेशी निवेश किया जाना संभव नही होगा।

प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (थ्क्) का विरोध :– भारत में FDI के सरकार के निर्णय पर भारी हंगामा और विरोध कायम है विपक्ष के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध के स्वर को प्रखर करते हुऐ ये आरोप लगाया कि सरकार खुदरा एवं अन्य क्षेत्रो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाह रही है सरकार ने हिदुंस्तान कापर, नालको, आयल इंडिया लि0 के विनिवेश को हरी झंडी दिखा कर सबका ध्यान FDI की ओर खींचना चाहती है तो दूसरी ओर म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने FDI का विरोध करते हुऐ इसे लाखो लोगो के रोजगार छीने जाने का कारण बताया । इसी प्रकार राज्य सभा मे विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने खुदरा व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय को विदेशी कंपनियों के लिऐ एक तोहफा बताते हुये कहा कि FDI के कारण देश के उद्योग और कृषि व्यवसाय चौपट हो जाऐगें।

तात्पर्य है है कि सरकार का दावा है कि यह नीति देश के लिए लाभदायक होगी तो विपक्ष का दावा है कि इस नीति से देश को हानि की सिवाए कुछ प्राप्त नही होगा, इसकी समीक्षा करने के लिए कि क्या वास्तव में FDI भारत के लिये वरदान साबित होगा या अभिशाप हमें प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के समर्थन में और प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के विरोध मे उठने वाले तर्को का आकलन करना होगा।

FDI के समर्थन मे तर्क – जब भारत में रिलायंस जैसी देश की सबसे बड़ी कम्पनी ने उपभोक्ता बाजार में अपनी घुसपैठ प्रारंभ की थी उस समय उसका प्रचुर मात्रा मे विरोध हुआ था लेकिन आज की परिस्थितियों में उपभोक्ता बाजार में उसका कोई विशेष प्रभाव नजर नही आ रहा है।

ठीक इस प्रकार जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था परन्तु आज की दशा में कंप्यूटर आम आदमी को आवश्यकता का एक भाग बन गया है तथा लाखों लोगो को रोजगार मुहैया कराये जाने का एक साधन भी बन गया है।

FDI ***के लाभो को निम्न बिदु से समझा जा सकता है :–***

(1) लोगों का यह तर्क है कि FDI से रोजगार में वृद्धि होगी क्योकि इस नियम के लागू होने पर पूरे देश में वस्तुओं के मूल्यों मे एकरूपता आ जाऐगी, लाखो लोगों की रोजगार प्राप्त होगा युवाओं को भिन्न – भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मिलेगें और उनके लिए संभावनाओं के नये रास्ते नये मार्ग प्रशस्त होगें।
(2) सरकार का यह तर्क है कि विदेशी कंम्पनियों के द्वारा किये जाने वाले निवेश से किसानो को अत्याधिक लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि FDI के शर्तों के अनुसार FDI में आने वाली कम्पनियों को कम से कम तीस प्रतिशत (30:) कच्चा माल भारतीय किसानो से ही खरीदना अनिवार्य होगा, इस कारण किसानो की स्थिति में सुधार होगा एवं प्रचुर मात्रा में माल बिकने की दशा में लाभ प्राप्त होगा।
(3) लोगो का तर्क है कि FDI से बिचौलियो की समाप्ति होगी तथा उपभोक्ताओ को लाभ प्राप्त होगा कारण ये है कि जब FDI के अर्न्तगत कम्पनीया प्रत्यक्ष निवेश करेगी तो बीच की मध्यस्था समाप्त जायेगी जिस कारण बिचौलियो का खात्मा हो जाऐगा और जब मध्यस्था करने वालो के द्वारा बीच में कमीशन खाने की प्रथा समाप्त होगी तो उपभोक्ताओं को जो समान प्राप्त होगा उसका मूल्य अपेक्षाकृत कम होगा, अर्थात ग्राहको को या उपभोक्ताओ को सस्ती दर पर सामान मिलेगा, साथ ही किसानो की आवश्यकता का कच्चा माल भी उन्हे सीधे कम्पनियो से प्राप्त होगा परिणाम स्वरूप किसानों को और कम्पनियो को दोनो को उचित लाभ की प्राप्ति होगी।
(4) ऐसा मानना है कि विदेशी निवेश प्राप्त होने की दशा में रूपये की खस्ता हालत में भी सुधार होगा जब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा के भंडार मे वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से रूपये की हालत में भी सुधार होगा।

FDI ***के विरोध में तर्क :–***

(1) FDI का विरोध करने वालो का ये तर्क है कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से होने वाले जिन फायदो को गिना रही है वो तथ्यहीन है जैसे यह कहा गया कि FDI से किसानो, उपभोक्ताओ और व्यापारियो का लाभ प्राप्त होगा और देश के बुनियादी ढांचे को भी FDI के माध्यम से उच्च स्तर पर लाया जा सकेगा किन्तु तथ्य बताते है कि जब अमेरिका मे वालमार्ट के स्टोर खुलने पर प्रारंभ हुये तो धीरे–धीरे करके वहाँ पर किराना स्टोर की 555 दुकाने, हार्डवेयर की 298 दुकाने सौन्दर्य प्रसाधन की 158 दुकाने मेडिकल की 116 दुकाने बंद हो गई। इसी प्रकार भारत के बड़े – बड़े शहरों में खुलने वाले विशाल मॉल्स के कारण स्थानीय व्यवसायियों और फेरी करने वाले व्यवसायियों के कारोबार पर पड़ने वाले ऋणात्मक प्रभाव का सर्वे किया गया है और ये पाया गया कि बड़ी मात्रा में खरीद करने वाले ग्राहक अब छोटे – छोटे दुकानदारों से माल खरीदने के बजाये इन बड़े – बड़े मॉल्स से माल का क्रय करते है जिससे इन छोटे व्यवसायियों के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई । अर्थात इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि FDI छोटे किराना दुकानदारों की लिये नुकसानदायक है।
(2) सरकार का यह तर्क कि विदेशी कम्पनियों के आने से वस्तुऐं सस्ती हो जाऐगी तथ्यहीन प्रतीत होता है क्योकि जब इस तेजी से बढ़ती हुई महगांई पर हमारी लोकतांत्रिक सरकारें लगाम लगाने में असमर्थ रहीं तो, बाहर से आने वाली कम्पनी इस पर रोकथाम किस प्रकार से कर पायेगी क्योंकि विदेशी कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य FDI के माध्यम से देश में प्रवेश कर अपनी लाभदायकता में वृद्धि करना है तो भला अपना लाभ घटाकर कोई दूसरे को लाभ क्यों पहुचाएंगा।
(3) वर्तमान समय में जहां सरकारी नौकरी ढूढ़े नही मिलती है तथा निजी क्षेत्र की नौकरी में प्रतिस्पर्धा चरम सीमा पर पहुंच गई है ऐसे में लोगो के द्वारा रोजी रोटी जुटाने और रोजगार की प्राप्ति के लिये व्यवसाय के अलावा अन्य कोई साधन नही बचता । भारत में खुदरा बाजार के द्वारा देश की आबादी के लगभग 4 प्रतिशत लोग रोजगार प्राप्त कर रहे है। और यह रोजगार लगभग 13: वार्षिक वृद्धि के साथ विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे में खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को मजूंरी मिलना रोजगार में कमी का द्योतक हो सकता है। देश में कृषि के बाद खुदरा व्यापार पर सर्वाधिक निर्भर है एक अनुमान के अनुसार देश में करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापार के पटल है जिसमें 30 से 35 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
(4) कार्पोरेट जगत के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि FDI से देश के किसान वर्ग को लाभ होगा परन्तु बिचौलियो तथा व्यापारी वर्ग की श्रँखला

के कारण किसानो को उनकी उत्पादित की गई उपज का उचित दाम नही मिल पाता इसके अलावा अब भारतीय कृषि उत्पादन सम्बंधी कानून भी पुराने हो चुके है जो ऐसी समस्या को हल कर पाने के लिये पर्याप्त नही है अर्थात विदेशी निवेश के भरोसे अधिक दिनों तक किसानों को रखा जाना न्याय संगत नहीं होगा। साथ ही इन विदेशी कम्पनीयों के द्वारा किसानों के शोषण किये जाने की सभांवना से भी इंकार नही किया जा सकता।

(5) FDI को लागू करने या ना करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया हैं जिसका परिणाम सरकारी अधिकारीयों तथा विदेशी कारोबारीयों के मध्य एक नये समीकरण को जन्म देगा और इसका परिणाम ये होगा कि खुदरा व्यापारियों को आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मुनाफा खोरी की प्रवृति में वृद्धि होगी जो निश्चित रूप से कही न कही भ्रष्टाचार तथा पूंजीगत विषमताओं को जन्म देगी। भारतीय विद्वानों का मत है जो काला धन पहले देश के बाहर चला गया था वह FDI के माध्यम से वापस देश में आ रहा है एक अनुमान के मुताबिक 80% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के रूप में कालेधन का ही निवेश किया जा रहा है जो भ्रष्टाचार जमाखोरी एवं कालेधन को बढ़ावा देने वाला कदम है।

निष्कर्ष एवं उपसंहार :–

FDI के समर्थन में और विरोध में उपरोक्त बिंदुओं की समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि खुदरा क्षेत्र में F.D.I के की अनुमति से देश को लाभ की तुलना में हानि बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के समर्थन में चाहे जितने तर्क प्रस्तुत किये जाये परतुं इससे होने वाली हानियो से आंखे बंद नही की जा सकती। सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता हैं कि FDI के अर्न्तगत आने वाली कम्पनीयों के कारोबार पर विशेष और पैनी निगरानी रखी जाये तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित और कठोर कदम उठाये जाऐ एवं इस सम्बंध में नियमो में कठोरता बरती जाऐ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

(1) हिन्दूस्तान टाइम्स न्यूज
(2) स्थानीय समाचार पत्र – दैनिक भास्कर
(3) मनोरमा ईयर बुक – 2012
(4) नवभारत समाचार पत्र, 30 सितम्बर 2011, 8दिसम्बर 2011, 14 दिसम्बर 2011
(5)जागरण जक्शन Post on – 23.09.2012
(6) वन इडिया हिन्दी समाचार पत्र 15.09.2012
(7) आई बी एन खबर – 19.07.2013